



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

ति4/ वित्तीय वर्ष 2025 के परिणाम

निवेशक मिलन

21मई, 2025

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्रबंधन:-

- श्रीमती परमिंदर चोपड़ा - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- श्री राजीव रंजन झा - निदेशक (परियोजना)
- श्री मनोज शर्मा - निदेशक (वाणिज्यिक)
- श्री संदीप कुमार - निदेशक (वित्त)
- श्री शशांक मिश्रा - सरकारी नामिती निदेशक
- श्री प्रसन्ना तंत्री - स्वतंत्र निदेशक
- सुश्री उषा सजीव नायर - स्वतंत्र निदेशक
- श्री नरेश धनराजभाई केल्ला- स्वतंत्र निदेशक
- श्री सुधीर मेहता - स्वतंत्र निदेशक

तुलनाकर्ता :

नमस्कार देवियों और सज्जनों। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया सुनिश्चित करें कि कार्यक्रम के दौरान आपके मोबाइल फोन सायरन या बजर मोड पर हों। धन्यवाद।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ओर से, हम इस निवेशक सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज कंपनी ने वर्ष 2024-25 के अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की है। पीएफसी का लक्ष्य सदैव अपने निवेशकों से जुड़ना तथा निवेशक समुदाय के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाना है। इसी उद्देश्य से आज का यह कार्यक्रम पीएफसी के वित्तीय प्रदर्शन और भावी संभावनाओं पर वर्तमान एवं भावी निवेशकों के साथ चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया है। अब मैं पीएफसी के प्रबंधन का परिचय देना चाहूंगा।

डेस्क पर, मेरे एकदम बाईं ओर, स्वतंत्र निदेशक श्री प्रसन्ना तंत्री जी हैं। सुश्री उषा सजीव नायर, (स्वतंत्र निदेशक), श्री मनोज शर्मा, (निदेशक वाणिज्यिक), श्री शशांक मिश्रा, (सरकारी नामित निदेशक), सुश्री परमिंदर चोपड़ा, (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक), श्री राजीव रंजन झा, निदेशक (परियोजना), श्री संदीप कुमार, (निदेशक वित्त), श्री नरेश धनराजभाई केल्ला, (स्वतंत्र निदेशक), और मेरे सबसे बाईं ओर (स्वतंत्र निदेशक) श्री सुधीर मेहता जी हैं। आज के वार्षिक निवेशक सम्मेलन का कार्यक्रम पीएफसी के सीएमडी के भाषण से आरंभ होगा, जिसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र आरंभ होगा।

अब मैं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुश्री परमिंदर चोपड़ा को सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा।

परमिंदर चोपड़ा:

सभी को शुभ संध्या और हार्दिक स्वागत है। आप सभी से फिर से जुड़ना हमेशा खुशी की बात होती है। हम वार्षिक वार्तालाप को बहुत महत्व देते हैं। यह हमें अपने सभी निवेशकों से सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। आज, हमने चौथी तिमाही एवं वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अपने परिणाम जारी किए हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएफसी ने एक बार फिर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। पीएफसी के समेकित परिणामों से शुरुआत करें तो हम 11.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक के समेकित बैलेंस शीट आकार के साथ भारत में सबसे बड़ा एनबीएफसी समूह बने हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए समेकित पीएटी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 15% वृद्धि के साथ 30,514 करोड़ रुपये रहा। समूह की ऋण परिसंपत्ति बही 11 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है और 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। परिसंपत्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर, हम अपने एनपीए स्तरों में कमी की प्रवृत्ति देख रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए समेकित शुद्ध एनपीए अनुपात वित्तीय वर्ष 2024 में 0.85% की तुलना में 0.38% है।

एकल प्रदर्शन की बात करें तो मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएफसी ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। पीएफसी ने 17,352 करोड़ रुपये का अपना सर्वकालिक उच्च वार्षिक लाभ दर्ज किया, जो वित्तीय वर्ष 2024 से 21% की प्रभावशाली वृद्धि है। लाभ में यह वृद्धि 24% की स्वस्थ शुद्ध ब्याज आय वृद्धि, प्रावधान प्रतिवर्तन और

समाधान के कारण वसूली से प्रेरित है। इसके साथ ही, पीएफसी भारत में सबसे अधिक लाभ कमाने वाली एनबीएफसी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है।

पीएफसी में हमेशा से ही शेयरधारकों के रिटर्न को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसी के अनुरूप, पीएफसी के बोर्ड ने आज 2.05 रुपये प्रति शेयर का अंतिम लाभांश घोषित किया है। पहले दिए गए 13.75 रुपये प्रति शेयर के संचयी अंतरिम लाभांश के साथ, वित्तीय वर्ष 25 के लिए कुल लाभांश 15.80 रुपये प्रति शेयर है। आज घोषित इस अंतिम लाभांश का भुगतान एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी के बाद किया जाएगा। हमारा लगातार बढ़ता लाभ हमें साल दर साल बेहतर रिटर्न देने में सक्षम बनाता है। पीएफसी हमेशा अपनी सफलता को साझा करने तथा अपने निवेशकों के लिए मूल्य सृजन करने की अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने हेतु प्रतिबद्ध है।

अब आइए प्रमुख वित्तीय संकेतकों पर चलते हैं। वित्तीय वर्ष 25 के लिए अनुपात स्थिर सीमा के भीतर बने हुए हैं। वित्तीय वर्ष 25 के लिए प्रतिफल 10.02% है, जिसमें फंड की लागत 7.44% है, जिसके परिणामस्वरूप स्प्रेड 2.58% पर हमारी निर्देशित सीमा के भीतर बना हुआ है। हम वित्तीय वर्ष 26 के लिए अपनी गाइडेंससीमा को लगभग 2.5% पर बनाए रखते हैं। वित्तीय वर्ष 25 के लिए शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.64% है।

पूंजी के मोर्चे पर, हमारे लगातार बढ़ते मुनाफे के साथ, पीएफसी की नेटवर्थ 31 मार्च, 2025 तक 90,937 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो साल-दर-साल 15% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 25 के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात 22.08% है, जो न्यूनतम नियामक आवश्यकताओं से काफी ऊपर है।

हमारी लगातार मजबूत वित्तीय स्थिति लचीलापन सुनिश्चित करती है और हमें लगातार विकसित होते बाजार परिवेश में मजबूत प्रदर्शन करने में सक्षम बनाती है।

अब मैं अपनी परिसंपत्ति गुणवत्ता पर अपडेट साझा करना चाहूंगी। जैसा कि हमने अपनी पिछली बातचीत में बताया है, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने चौथी तिमाही से 2025 के दौरान 3,300 करोड़ रुपये की केएसके महानदी परियोजना का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया है। केएसके 3,600 मेगावॉट की कोयला आधारित परियोजना है और इसका समाधान एनसीएलटी के माध्यम से किया गया है। केएसके के लिए 4,448 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावे के मुकाबले, पीएफसी को 100% मूलधन वसूली मिली और हमें ब्याज आय के मुकाबले 1,192 करोड़ रुपये भी मिले हैं। इसके परिणामस्वरूप स्वीकृत दावे से अधिक की वसूली हुई है। इसके अलावा, इस परिसंपत्ति पर 55% प्रावधान, जो लगभग 1,815 करोड़ रुपये है, को ति4-2025 में वापस ले लिया गया है।

इसके साथ ही हमारा शुद्ध एनपीए अनुपात घटकर आधा प्रतिशत से भी कम हो गया है, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे कम है और पिछले वित्तीय वर्ष के 0.85% की तुलना में 0.39% है।

सकल एनपीए 1.94% पर है, जो परिसंपत्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार को दर्शाता है।

समाधान के बाद, स्टेज 3 बुक 21 परियोजनाओं के साथ 10,517 करोड़ रुपये पर है। इन परियोजनाओं में से, 8,209 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं का समाधान एनसीएलटी के माध्यम से किया जा रहा है, जिनमें से 2,605 करोड़ रुपये की 6 परियोजनाएं परिसमापन के अधीन हैं। जबकि 2,308 करोड़ रुपये की शेष 11 परियोजनाओं का समाधान एनसीएलटी के बाहर किया जा रहा है। जैसा कि पहले बताया गया था, 1,661 करोड़ रुपये की 2 परियोजनाएं समाधान के उन्नत चरण में हैं। ये दोनों परियोजनाएं एनसीएलटी के बाहर हैं।

पहला है टीआरएन एनर्जी प्रोजेक्ट, जिस पर 1,139 करोड़ रुपए बकाया है। यह 600 मेगावाट का थर्मल प्लांट है। हमने इसके लिए करीब 50% प्रावधान बनाए रखा है।

दूसरा है शिगा एनर्जी प्रोजेक्ट, जिस पर 522 करोड़ रुपये का बकाया लोन है। यह 97 मेगावाट का चालू हाइड्रो एनर्जी प्लांट है और हम करीब 31% का प्रावधान बनाए हुए हैं। टीआरएन एनर्जी और शिगा एनर्जी दोनों के लिए, पुनर्गठन योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और दस्तावेजीकरण और वर्तमान में कार्यान्वयन प्रक्रिया चल रही है। दोनों परियोजनाओं पर, हमने पर्याप्त प्रावधान बनाए रखा है।

इसके अलावा मैं कुछ अन्य प्रमुख संकटग्रस्त परियोजनाओं पर भी अपडेट देना चाहूंगी। इनमें से एक सिन्नर थर्मल पावर परियोजना है, जिस पर 3,000 करोड़ रुपये की बकाया राशि है। यह 1,350 मेगावाट का कोयला आधारित संयंत्र है, जिसका समाधान एनसीएलटी के तहत किया जा रहा है। परियोजना के लिए समाधान प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा चल रही है। वर्तमान में हमने परियोजना पर 80% प्रावधान बनाए रखा है।

दूसरा मामला इंडिया पावर हल्दिया का है, जिस पर 959 करोड़ रुपए बकाया है। यह 450 मेगावाट का कोयला आधारित प्लांट है और इसका समाधान एनसीएलटी के तहत किया जा रहा है। समाधान योजना के लिए आवेदन 23 दिसंबर, 2024 को एनसीएलटी के समक्ष दायर किया गया है। वर्तमान में हम इस परियोजना पर 50% प्रावधान बनाए हुए हैं।

कुल स्टेज 3 एसेट पोर्टफोलियो पर, हम 80% का स्वस्थ प्रावधान बनाए रखना जारी रखते हैं। प्रावधान के संबंध में, मैं फरवरी, 2025 में की गई 13वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज की रिलीज पर प्रकाश डालना चाहूंगी। पीएफसी पिछले कई वर्षों से इस अभ्यास के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। यह रिपोर्ट देश भर में बिजली वितरण कंपनियों के परिचालन प्रदर्शन के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करती है और इसे परिचालन सुधार लाने के एक प्रभावी तरीके के रूप में देखा जाता है।

प्रावधान के उद्देश्य से, पीएफसी अपेक्षित क्रेडिट लॉस मॉडल का पालन कर रहा है, जिसमें वित्तीय मापदंडों के साथ-साथ परिचालन मापदंडों पर भी विचार किया जाता है। तदनुसार, इन रेटिंग्स में दर्शाई गई डिस्कॉम द्वारा प्राप्त परिचालन दक्षताओं को भी ईसीएल प्रावधान में शामिल किया जाता है। इस रिपोर्ट में 15 डिस्कॉम की रेटिंग को अपग्रेड किया गया। जबकि 13 डिस्कॉम की रेटिंग में गिरावट आई।

तदनुसार, केएसके महानदी से प्रावधान प्रत्यावर्तन का उपयोग इन रेटिंग परिवर्तनों के लिए लगभग 900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान बनाने के लिए किया गया है।

प्रावधान के बारे में बात करते हुए, मैं जेनसोल इंजीनियरिंग का भी उल्लेख करना चाहूंगी। इस परियोजना के बारे में बहुत चर्चा हुई है। पीएफसी ने 3000 इलेक्ट्रिक वाहनों को पट्टे पर देने के लिए जेनसोल को 352 करोड़ रुपये संवितरित किए थे। अब तक 2741 वाहन वितरित किए जा चुके हैं और पीएफसी को बंधक बनाए गए हैं। अप्रैल में पीएफसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जेनसोल की बकाया ऋण राशि 307 करोड़ रुपये थी। इसके बाद, हमने सावधि जमा और टीआरए खाते की शेष राशि के सुरक्षा नकदीकरण के माध्यम से 44 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं।

चौथी तिमाही में, हमने 263 करोड़ रुपये के मौजूदा बकाया के साथ एनपीए जेनसोल इंजीनियरिंग पर 100% प्रावधान किया है। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगी कि यह एक प्रमोटर-विशिष्ट घटना है और हम इसे क्षेत्रीय जोखिम का प्रतिनिधित्व करते हुए नहीं देखते हैं। यह परियोजना पीएफसी की मूल्यांकन पद्धति या पीएफसी द्वारा अपनाई गई जोखिम शमन रणनीतियों को प्रतिबिंबित नहीं करती है। मैं दोहराना चाहूंगी कि एनपीए किसी भी वित्तीय संस्थान के लिए एक सामान्य व्यावसायिक जोखिम है। हमारी ऋण पुस्तिका परिसंपत्ति पर मजबूत प्रावधान सही और निष्पक्ष वित्तीय दिखाने के लिए हमारे विवेकपूर्ण और पारदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

अब, ऋण परिसंपत्ति वृद्धि पर आते हैं। पिछले साल की निवेशक बैठक में, हमने ऋण वृद्धि के लिए पीएफसी द्वारा अपनाई गई 3आर रणनीति की रूपरेखा तैयार की थी, जो यथार्थवादी, लचीले और मजबूत तरीके से वृद्धि है। इन 3 स्तंभों द्वारा निर्देशित, मुझे यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने वित्तीय वर्ष 25 में 12.81% की ऋण परिसंपत्ति वृद्धि हासिल की है, जो पूरे वर्ष हमारे द्वारा दिए गए स्प्रेड गाइडेंस के अनुरूप है।

अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो पर भी हमारा पोर्टफोलियो 81,031 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 35% की वृद्धि है, और हमने देश में सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा वित्तीयपोषण एजेंसी की अपनी स्थिति को बरकरार रखा है। मुख्य विकास चालक वितरण और अक्षय ऊर्जा थे, जिन्होंने कुल संवितरण में 55% और 17% का योगदान दिया।

अब वित्तीय वर्ष 26 के लिए ऋण वृद्धि रणनीति पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अपने 2030 ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 25 में लगभग 30 गीगावॉट की रिकॉर्ड अक्षय क्षमता वृद्धि देखी गई, जिसमें सौर ऊर्जा इन कुल वृद्धि का 80% हिस्सा थी।

इसके अलावा, फरवरी 2024 में शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान दे रही है। मार्च 2025 तक, इस योजना ने 10 लाख से ज्यादा घरों को कवर करते हुए 3 गीगावॉट से ज्यादा की छत पर सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, इस योजना के तहत 27 मार्च तक 27 गीगावॉट का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में, भारत में 17 गीगावॉट से ज्यादा की छत पर सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता है। इससे मार्च 2025 तक भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए कुल स्थापित क्षमता 220 गीगावॉट हो जाती है, जो देश की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 45% है।

भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए उम्मीद है कि अक्षय ऊर्जा हमारी कुल स्थापित क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। अक्षय ऊर्जा की अस्थायी प्रकृति को देखते हुए, ग्रिड स्थिरता और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। सरकार तीन गुना तरीके से ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पहला है अक्षय ऊर्जा को ऊर्जा भंडारण समाधान के साथ एकीकृत करके इसे दृढ़ और प्रेषण योग्य बनाना। दूसरा, थर्मल उत्पादन क्षेत्र में क्षमता वृद्धि के साथ अक्षय ऊर्जा को रणनीतिक रूप से पूरक बनाना। और तीसरा परमाणु उत्पादन क्षमता के विस्तार की खोज करना। इस फोकस के साथ संरेखित, नए अक्षय ऊर्जा विकल्प एकीकृत परियोजनाओं जैसे कि सौर-पवन संकर और बैटरी ऊर्जा भंडारण या पंप भंडारण परियोजनाओं के साथ युग्मित उत्पादन परियोजनाओं पर तेजी से जोर दे रहे हैं।

उदाहरण के लिए, 2025 में, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भविष्य की सौर निविदाओं में न्यूनतम 2 घंटे की सह-स्थित ऊर्जा भंडारण प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2025 में, कुल नीलामी क्षमता का 50% से अधिक एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा के लिए था।

मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहती हूँ कि ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण तकनीक, विशेष रूप से बैटरी ऊर्जा भंडारण, अभी भी विकास और अपनाने के अपने शुरुआती चरण में है, न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर। जैसे-जैसे अपनाने की दर बढ़ेगी, वैसे-वैसे तेज़ी से होने वाली तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप लागत में कमी और दक्षता में वृद्धि होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना का शुल्क जो 2022 में लगभग 8 से 10 रुपये प्रति यूनिट था, अब घटकर 6 से 7 रुपये प्रति यूनिट हो गया है। टैरिफ़ में यह कमी आने वाली प्रवृत्ति भविष्य में महत्वपूर्ण पैमाने को प्राप्त करने में मदद करेगी। यह स्थिति भारत में सौर पीवी परियोजनाओं के शुरुआती दिनों को दर्शाती है। ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र का विकास भविष्य के अक्षय ऊर्जा विकास के लिए महत्वपूर्ण

होगा। जिस तरह हम अक्षय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं का समर्थन करने में अग्रणी थे, उसी तरह पीएफसी इन उभरती प्रौद्योगिकियों को वित्तीयपोषित करने में सबसे आगे रहने के लिए प्रतिबद्ध है।

अब हम ऊर्जा सुरक्षा के दूसरे पहलू पर आते हैं, जो थर्मल क्षमता वृद्धि है। इस वर्ष की शुरुआत में, सरकार ने 80 गीगावाट थर्मल उत्पादन क्षमता जोड़ने की अपनी योजना की घोषणा की है। थर्मल पावर परियोजना की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने की समय-गहन प्रकृति को देखते हुए, हम यह कल्पना करते हैं कि इस क्षेत्र में वित्तीय पोषण के अवसर मध्यम अवधि में साकार होंगे, जो पीएफसी के लिए एक महत्वपूर्ण मध्यम अवधि विकास मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है।

तीसरे क्षेत्र की बात करें तो यह परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार है। इसके लिए भारत सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया है, जिसमें 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के विकास की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, यह आगे चलकर पीएफसी के लिए ऋण देने का एक और अवसर होगा।

बिजली वितरण के मोर्चे पर बात करें तो पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में वित्तीयपोषण मुख्य रूप से एलआईएस और एलपीएस जैसी सरकारी योजनाओं के कारण हुआ है, जिन्हें अब पर्याप्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। आरडीएसएस योजना चल रही है और हमारे पास वर्तमान में लगभग 39,000 करोड़ रुपये की मंजूरी है। पिछले डेढ़ साल में, हमने राज्य डिस्कॉम को बिल भुगतान सुविधाओं या आरबीपीएफ के माध्यम से वित्तीयपोषण पर भी ध्यान केंद्रित किया है। हमें उम्मीद है कि यह इस साल भी जारी रहेगा। वितरण क्षेत्र की वृद्धि के लिए, आरडीएसएस योजना में प्रगति और इस क्षेत्र को समर्थन देने के लिए सरकार के किसी भी नए उपाय पर नज़र रखना महत्वपूर्ण होगा।

बिजली क्षेत्र की मौजूदा गतिशीलता को देखते हुए, हमारा मानना है कि विकास एक ही खंड के बजाय कई मोर्चों से प्रेरित होगा। बिजली क्षेत्र हमारा प्राथमिक ध्यान बना हुआ है। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर, हम क्रमिक तरीके से विकास की अपनी रणनीति को जारी रखेंगे। तदनुसार, विभिन्न खंडों में मौजूदा विकास गति को देखते हुए और 3आर, यथार्थवादी, लचीला और मजबूत ऋण वृद्धि के हमारे आदर्श वाक्य द्वारा निर्देशित, हम 10-11% की ऋण वृद्धि की उम्मीद करते हैं।

वित्तीय वर्ष 25 में, हमने वह सब कुछ किया जो हमने पूरे साल वादा किया था। वर्तमान में, हमारी लोन बुक लगभग 5.43 लाख करोड़ है। इतनी बड़ी बुक पर वृद्धिशील वृद्धि के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी नई लोन परिसंपत्तियाँ इस तरह से जोड़ी जाएँ कि दीर्घ अवधि में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित हो, निरंतर बॉटम लाइन प्रदर्शन हो, और मजबूत परिसंपत्ति गुणवत्ता बनी रहे। ये मूल सिद्धांत आगे चलकर हमारी लोन वृद्धि रणनीति को परिभाषित करना जारी रखेंगे।

अब उधारी के मोर्चे पर चलते हैं, पिछले साल हमने 1.11 लाख करोड़ की राशि सफलतापूर्वक जुटाई। एक अच्छी तरह से विविधीकृत फंडिंग पोर्टफोलियो को बनाए रखने की हमारी रणनीति के अनुरूप, हमारे द्वारा जुटाई गई राशि का लगभग 76% घरेलू स्रोतों से आया, जबकि 24% विदेशी मुद्रा उधार के माध्यम से था। वर्तमान में, हमारे पास जी3 मुद्राओं में विदेशी मुद्रा जोखिम है, जिसमें लगभग 70% जोखिम अमेरिकी डॉलर में है। विदेशी मुद्रा उधारी की बात करते हुए, मैं सक्रिय ट्रेजरी के माध्यम से विदेशी मुद्रा जोखिमों के प्रबंधन के लिए हमारे सक्रिय दृष्टिकोण को उजागर करना चाहूंगी। अभी, हमारे पोर्टफोलियो का 95% विनिमय जोखिम के लिए सुरक्षित है। अमेरिकी डॉलर में नामित पोर्टफोलियो के लिए लगभग 100% विनिमय दर जोखिम सुरक्षित है।

अंत में, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि हम उभरते ऊर्जा परिदृश्य को नेविगेट करने, उभरते अवसरों का लाभ उठाने और अपने हितधारकों को स्थायी मूल्य प्रदान करने की अपनी क्षमता पर आश्वस्त हैं।

धन्यवाद

तुलनाकर्ता:

धन्यवाद मैम, देवियों और सज्जनों, अब हम प्रश्नोत्तर सत्र शुरू करेंगे, जैसे ही आप अपना हाथ ऊपर उठाएंगे, एक स्वयंसेवक माइक लेकर आपके पास आएगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपना और अपनी कंपनी का परिचय दें। और हमारे प्रतिभागियों से भी अनुरोध है कि वे अपने प्रश्नों को अधिकतम एक या दो तक ही सीमित रखें ताकि सभी को बातचीत करने का अवसर मिले। धन्यवाद।

हां, हम आपसे शुरुआत करेंगे।

अभिजीत टिबरेवाल:

मेरा प्रश्न लेने के लिए धन्यवाद। मैं मोतीलाल ओसवाल से अभिजीत टिबरेवाल हूँ। सबसे पहले, आज इस सत्र की मेजबानी के लिए धन्यवाद, मैडम। मेरा प्रश्न यह समझने का प्रयास था कि जब हम विकास की तुलना में देखते हैं कि हम कहाँ थे, तो जाहिर है, लोन बुक का आकार बढ़ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं हम यह भी देख रहे हैं कि स्प्रेड गाइडेंस के संदर्भ में, हमने और साथ ही आरईसी ने पहले, अपने ऋण वृद्धि स्प्रेड गाइडेंस कम किया है। तो पिछले छह, नौ महीनों में वास्तव में क्या बदलाव आया है, जो स्प्रेड गाइडेंस में इस नरमी को प्रेरित कर रहा है? सरकार ने वास्तव में अपनी योजनाओं में कोई बदलाव नहीं किया है कि हम थर्मल, नवीकरणीय पर कितनी स्थापित क्षमता जोड़ना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों प्रेरित कर रहा है? और मैडम यहाँ एक संबंधित प्रश्न यह भी है कि, मेरा मतलब है, हम भूमि अधिग्रहण के मुद्दों, रास्ते के अधिकार के बारे में सुनते रहते हैं। तो, मेरा मतलब है, ये परियोजनाओं के चालू होने में देरी कर रहे हैं,

है न? और पीपीए पर हस्ताक्षर कमजोर हैं। मेरा मतलब है, क्या ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे स्प्रेड गाइडेंस को कम करने की ओर ले जा रही हैं या क्या कुछ और है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए? धन्यवाद।

परमिंदर चोपड़ा:

जैसा कि मैंने अपनी टिप्पणी में आपको बताया था कि चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धि मुख्य रूप से वितरण क्षेत्र से आई है, जो 55% संवितरण है और उसके बाद नवीकरणीय क्षेत्र है, जो 17% है। जब हम वितरण क्षेत्र की बात करते हैं, तो दो प्रमुख योजनाएं- एलआईएस पहले ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन एलपीएस योजना के तहत संवितरण किया जा रहा था, जो हम देख रहे हैं कि लगभग समाप्त हो गया है और बहुत, बहुत कम संवितरण ही हैं, जिसकी हम चालू वित्तीय वर्ष 26 में उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए आगे बढ़ने वाला यह बड़ा बदलाव है। और निश्चित रूप से, एक बार जब संवितरण कम हो जाता है, तो विकास भी पहले से ही प्रभावित होने वाला है।

यदि आपने पिछले वर्ष देखा है, तो हम देख रहे हैं कि हम 12 से 13% की दर से वृद्धि करने जा रहे हैं। हमने वृद्धि के लिए अपने स्प्रेड गाइडेंस में कोई खास कमी नहीं की है। हमने कहा है कि यह केवल 10 से 11% है और विस्तारित विभाजक पर वृद्धि हो रही है, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यह कैसे आगे बढ़ने जा रहा है। तो यही एकमात्र कारण है। आपकी अगली चिंता भूमि मुद्दे, मार्ग के अधिकार, पीपीए पर हस्ताक्षर न होने के बारे में थी। मुझे लगता है कि हाँ, मैं सहमत हूँ कि ये क्षेत्रीय मुद्दे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कारक हमारे विकास को किसी बड़े तरीके से बाधित करने जा रहे हैं। धन्यवाद।

अभिजीत टिबरेवाल:

हाँ, महोदया।

श्रेया शिवानी:

हाँ। नमस्ते। मेरा नाम श्रेया है और मैं सीएलएसए से हूँ।

मेरा सवाल यह है कि अगर मैं एक दशक पहले संवितरण बनाम मंजूरी को पिछले तीन वर्षों में क्या चलन रहा है, तो स्पष्ट रूप से मंजूरी, संवितरण तीन साल की अवधि की तुलना में बहुत कम रहा है, अगर मैं वित्तीय वर्ष 14, 15, 16, आदि से तुलना करती हूँ। इसलिए, मैं आपके द्वारा बताए गए कारणों के अलावा मंजूरी और संवितरण के बीच के अंतर को समझना चाहती थी। कुछ अतिरिक्त प्रक्रियाएँ या अतिरिक्त स्वीकृतियाँ क्या हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं, जो हम एक दशक पहले नहीं कर रहे थे? तो बस यह समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या परिचालनात्मक रूप से हमारी प्रक्रियाओं में कुछ बदलाव आया है, जिस तरह से हम मंजूरी से लेकर संवितरण तक की गति से निपट रहे हैं।

परमिंदर चोपड़ा:

जैसा कि आप पहले बता रही थीं, हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में प्रतिबंध हैं, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि उस समय ये प्रतिबंध कहाँ से आ रहे थे, बड़ी संख्या में थर्मल परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही थी, जो उच्च मूल्य की थीं। प्रत्येक थर्मल परियोजना में बहुत बड़ा पूंजीगत व्यय होता है। और क्षमताएँ भी उन संख्याओं के मुकाबले बहुत बड़ी थीं। अगर हम वर्तमान संदर्भ में देखें, तो अधिकांश प्रतिबंध नवीकरणीय, पुनर्वित्तपोषण से आ रहे हैं, जहाँ गर्भावधि बहुत कम है। इसलिए और मात्रा कम है, हम एक नवीकरणीय परियोजना बनाम एक थर्मल परियोजना की तुलना करते हैं, नवीकरणीय परियोजना- क्षमताएँ कम हैं, और तदनुसार पूंजीगत लागत भी है और परियोजना लागत भी कम है। प्रतिबंधों की संख्या अधिक हो सकती है। लेकिन प्रत्येक परियोजना के लिए मात्रा और इसलिए समग्र मंजूरी चक्र अलग-अलग हो सकता है।

श्रेया शिवानी:

समझ गई। तो यही प्रवाह के माध्यम मुख्य कारण है। और बस उस पर आगे बढ़ते हुए, हमने जिन सभी मुद्दों पर बात की, जैसे कि पीपीए कम होना, धीमा पड़ना, आदि। क्या समाधान वास्तव में अधिक से अधिक, आप जानती हैं, क्षेत्रीय इकाई, सरकारी निकायों या जैसे, से आएगा, इसका कोई समाधान होना चाहिए, है ना? यह किसी एक कंपनी से नहीं होगा। यह अधिक से अधिक, बड़े शासी निकायों से होगा। तो क्या यही इसका समाधान है? मैं बस समझने की कोशिश कर रही हूँ। इसका समाधान कैसे होगा? धन्यवाद।

परमिंदर चोपड़ा:

मुझे लगता है कि इस पर सरकारी स्तर पर उचित विचार किया जा रहा है। चाहे वह अधिकार का मुद्दा हो या पीपीए न आना हो, या विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए निकासी सुविधा हो, कुछ क्षेत्रों में पीपीए पर हस्ताक्षर न होने की वजह से यह उच्चतम स्तर पर रहा है, जैसा कि मैं कहूँगी कि विद्युत मंत्रालय के स्तर पर, इस पर विचार किया जा रहा है।

श्वेता:

एलारा से श्वेता, अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैडम, आप प्रतिबंधों के सवाल को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगी। तो तीसरी तिमाही में, आपने बताया था कि प्रतिबंधों की संख्या लगभग दो लाख, 50,000 करोड़ थी। ठीक है। तो वित्तीय वर्ष 25 के अंत तक संख्या क्या है? और अगर मैं पिछले साल की संख्या को देखूँ, तो यह लगभग दो लाख 80,000 करोड़ थी। तो आगे बढ़ते हुए, इसमें मुख्य योगदानकर्ता कौन हैं या इस प्रतिबंध संख्या के मुख्य घटक क्या हैं? बिंदु संख्या एक। बिंदु संख्या दो, अपनी शुरुआती टिप्पणियों में, आपने वितरण पक्ष पर उल्लेख किया कि एलपीएस अब लगभग पीछे है, आरडीएसएस कुछ ऐसा है, जो संभवतः आगे वितरण को आगे बढ़ाएगा। लेकिन पूरे वित्तीय वर्ष 25 के लिए, हमने आरबीपीएफ देखा है, जो बड़े पैमाने पर वितरण ऋण वितरण को आगे बढ़ा रहा था। आपने यह भी उल्लेख किया कि यह बरकरार रहेगा। तो आरडीएसएस वितरण पर प्रगति कैसी है सरकारी अनुदान घटक बनाम पीएफसी, आरईसी

घटक आगे विकास के लिए एक लीवर के रूप में कार्य करेगा। और आखिरी लेकिन कम महत्वपूर्ण बात यह है कि निजी क्षेत्र के तीसरे चरण में, जो कि लगभग 1.94 है, पिछले वर्ष की तुलना में 2.7 से कम हो गया है। तो क्या यह उन संकल्पों के कारण है जो पहले ही हो चुके हैं? तो, इससे मेरा तात्पर्य है, क्या ये विरासत संपत्तियाँ हैं या कोई नया ताज़ा जोड़ हो रहा है? आप जानते हैं, जो हाल ही की अवधि में हुआ हो सकता है। धन्यवाद।

परमिंदर चोपड़ा:

देखिए, डिस्कॉम की तरफ से आरडीएसएस योजना है। मैंने आपको बताया कि काउंटरपार्ट फंडिंग के तहत हमारे पास करीब 38,000-39,000 रुपये की असंवितरित मंजूरी है। इसलिए सभी जानते हैं कि आरडीएसएस योजना शुरू की गई थी और टेंडर लगाने में कुछ देरी हुई थी। इसलिए अब टेंडर लगा दिए गए हैं। इसलिए जो काम लगभग शुरू हो चुका है, वह पूरे जोरों पर होने वाला है। सबसे पहले सरकारी अनुदान जारी किया जाएगा और उसके बाद काउंटरपार्ट फंडिंग लागू होगी। तो यह तरीका है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि चालू वित्तीय वर्ष में पिछले साल की तुलना में हमारे पास अधिक प्रतिस्पर्धी संवितरण होगा।

तुलनाकर्ता:

हाँ, वहाँ पर जो सज्जन हैं,

श्रीपाल:

नमस्ते मैडम, श्रीपाल, इक्विरस से। तो, मेरा प्रश्न संवितरण पर था, चूंकि हमारा अधिकांश संवितरण 26 में नवीकरणीय और डिस्कॉम की ओर होने वाला है, क्या आप देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 26 से या वित्तीय वर्ष 25 की तुलना में मार्जिन संकुचित हो रहा है। और दूसरा प्रश्न पुनर्भुगतान पर था। तो, इस साल पुनर्भुगतान या पूर्वभुगतान थोड़ी नरम वृद्धि के पीछे एक कारण रहा है। तो क्या आपको लगता है कि यह वित्तीय वर्ष 26 में भी जारी रहेगा। धन्यवाद।

परमिंदर चोपड़ा:

स्प्रेड के मोर्चे पर देखें, मैंने पहले ही स्प्रेड गाइडेंस दिया है कि हम इसे लगभग 2.5% की हमारी पूर्व निर्देशित सीमा के भीतर बनाए रखने जा रहे हैं। आपके प्रीपेमेंट मामले पर, प्रीपेमेंट। मैं जो समझती हूँ, वह यह है कि प्रत्येक वित्तीय संस्थान के लिए व्यवसाय के सामान्य क्रम में क्या होता है। हाँ, मैं सहमत हूँ, कुछ वर्षों में बहुत अधिक प्रीपेमेंट होते हैं और कुछ वर्षों में प्रीपेमेंट उस स्तर पर नहीं हो सकता है, लेकिन हमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान हर बार स्प्रेड गाइडेंस दिया गया है कि हमारी वृद्धि की उम्मीद लगभग 12 से 13% है, और हमने यही किया है। इसलिए मुझे लगता है कि सभी तथ्यों पर विचार करते हुए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह इस वित्तीय वर्ष में 10 से 11% की वृद्धि होगी।

चिंतन शाह:

हाँ। अवसर के लिए धन्यवाद। और मैं चिंतन शाह हूँ, आईसीआईसीआई सिक्क्योरिटीज से। तो, मैडम, पिछले तीन वर्षों में, हम लगभग 13% की सीएजीआर से बढ़े हैं। यह, जिसमें निजी क्षेत्र लगभग 28 से 30% सीएजीआर से बढ़ा है। जबकि सरकारी क्षेत्र की वृद्धि लगभग 10% है। और पिछले तीन वर्षों में संपत्ति की गुणवत्ता भी अभूतपूर्व रही है, संकल्पों और कोई नई गिरावट नहीं होने से सहायता मिली है। लेकिन, हम आगे चलकर संपत्ति की गुणवत्ता के रुझान को कैसे देखते हैं, यह देखते हुए कि हम काफी हद तक बढ़े हैं, साथ ही इस निजी क्षेत्र की वृद्धि पुस्तक, जो पिछले तीन वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है। तो इन ऋणों का व्यवहारिक कार्यकाल क्या होगा? हाँ। धन्यवाद।

परमिंदर चोपड़ा:

देखिए, निजी क्षेत्र के बारे में, जैसा कि मैंने आपको आरंभिक टिप्पणियों में बताया था, हर कोई जानता है कि विकास या तो वितरण क्षेत्र से या नवीकरणीय से आ रहा है और नवीकरणीय मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में रहा है। इसलिए वे सभी संवितरण नवीकरणीय निजी क्षेत्र में हुए हैं। और इस तरह आप सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच हमारे विभाजन में बदलाव देख रहे हैं। आगे भी, हम बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा के लिए और सरकार, दृष्टिकोण, निजी क्षेत्र से अधिक से अधिक भागीदारी के अनुरूप वित्तीय पोषण की तलाश कर रहे हैं। हमारा वित्तीय पोषण भी उसी दिशा में जाने वाला है। इस प्रकार, यदि आप पहले सरकारी क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहां बड़ी विद्युत उत्पादन परियोजनाएं थीं, जिनके सरकारी क्षेत्र में आने की उम्मीद थी, तथा पीएफसी कंसोर्टियम फंडिंग का हिस्सा था। इसलिए अब सरकारी क्षेत्र में प्रमुख संवितरण डिस्कॉम की ओर है और डिस्कॉम - प्रमुख वित्तीय पोषण की आवश्यकता एलआईएस, एलपीएस जैसी सरकारी योजनाओं के वित्तीय पोषण के लिए आ रही है और हाल ही में हमने आरबीपीएफ को वित्तीय पोषित किया है। इस प्रकार आप पीएफसी के खाते में सरकार की तुलना में निजी क्षेत्र की ओर अधिक झुकाव देख रहे हैं।

प्रशांत:

मिलेनियम से प्रशांत। यहाँ पहले से पूछे गए प्रश्नों के अनुवर्ती प्रश्न, 2.5% प्रसार के साथ 10 से 11% वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। क्या इसमें यह ध्यान में रखा गया है कि हम रेपो दर में कटौती के चक्र में हैं और बहुत से पीएसयू बैंक रेपो से जुड़े ऋणों का पूरा पास-श्रू करने जा रहे हैं। तो क्या आपको पीएसयू बैंकों से मार्जिन या प्रीपेमेंट पर कुछ दबाव की उम्मीद है, जिसकी चर्चा की गई थी, जो इस बार, पिछले चक्र के विपरीत, बहुत अधिक पूंजीकृत हैं, बहुत अधिक साफ-सुथरी बैलेंस शीट हैं। तो, क्या इससे आपके मार्जिन या आपकी वृद्धि दर पर कोई दबाव है? तो यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, आपने जेनसोल के बारे में बात की, जो एक प्रमोटर मुद्दा है। क्या आप किसी अन्य संभावित, प्रमोटर मुद्दों या किसी अन्य प्रकार के मुद्दों, किसी भी स्लिपेज को चिह्नित करना चाहेंगी, जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं, हम एक निवेशक समुदाय के रूप में आपके पास नकारात्मक स्लिपेज होने के आदी हो गए हैं, क्या हमें किसी भी स्लिपेज के बारे में पता होना चाहिए, कम से कम सकल आधार पर, आने वाला है? और यदि ऐसा है, तो आप उनमें से कुछ को परिमाणित करना चाहेंगे। और अंत में, एक बड़ा सवाल, जैसे कि हाल ही में, आपने पिछले वर्ष भी देखा है कि सरकार ने पूंजीगत व्यय से हटकर उपभोग की ओर अधिक ध्यान दिया है, चाहे वह राज्य बजट का पुनर्आवंटन हो या सरकारी बजट का।

और हमारे आधे से अधिक संवितरण के संदर्भ में, वितरण के लिए राज्य सरकारों को, क्या आपको चिंता है कि अब राज्य सरकारों में अपनी बैलेंस शीट को बनाए रखने के लिए अनुशासन की कमी है और इसलिए, क्या इस राज्य बिजली दोनों का घाटा फिर से बढ़ने लगा है? यदि आप कर सकें, तो उन तीन सवालों के बारे में अपने विचार दें।

परमिंदर चोपड़ा:

किसी भी वित्तीय संस्थान के लिए पैसा कच्चे माल की तरह काम करता है। इसलिए जब हम फंड उधार लेते हैं, तो हम जिस भी दर पर फंड उधार लेते हैं, वह आउटपुट की एक बड़ी लागत भी होती है। इसी तरह पीएफसी के लिए, जब हम फंड उधार लेते हैं, अगर हम कम दर पर जुटाने में सक्षम हैं, तो निश्चित रूप से। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम अपने स्प्रेड गाइडेंस को बनाए रखने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी उधार दर कम नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन हां, मैं सहमत हूँ कि आपने जिस तरह से कहा कि किसी भी बैंक के लिए, रेपो दर में कमी हमारे मुकाबले उधार लेने की लागत को कम करने में बड़ा प्रभाव डालती है, जहां हमारे पास अधिकांश वाणिज्यिक उधार हैं, वह भी बॉन्ड मार्केट से, जो कमोबेश प्रकृति में तय है। लेकिन फिर भी, चूंकि हमारे पास चार, साढ़े चार साल की औसत देयता अवधि है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारा 25% उधार चुकाया जाएगा। और जो भी उधार हम नया ले रहे हैं, वह मौजूदा बाजार दर पर वापस आने वाला है। ठीक है, संक्रमण धीमा हो सकता है। मैं सहमत हूँ कि ऐसा हमेशा होता रहा है और हमारे उधारकर्ता इसे अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे ब्याज दर में वृद्धि हो या ब्याज दर में कमी हो, दोनों ही मामलों में पीएफसी के लिए बैंकों की तुलना में परिवर्तन धीमा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक बुनियादी ढांचा वित्तीय कंपनी होने के नाते, इसका व्यवसाय अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा छीन लिया जा सकता है। इस क्षेत्र में अन्य सीमाएँ भी हैं, जो हमेशा हो सकती हैं। हम बैंकों से उधार ले रहे हैं, इसलिए बैंक हमेशा पीएफसी की तुलना में किसी भी समय सस्ती दर पर उधार दे सकते हैं, चाहे उच्च ब्याज दर परिरक्ष्य हो या कम ब्याज दर परिरक्ष्य। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह कोई चुनौती है। ठीक है। और हम स्वीकार करते हैं कि पूर्व भुगतान व्यवसाय का अभिन्न अंग है। तो यह एक अपेक्षित बात है। स्लिपेज के बारे में आपके अगले मुद्दे पर। मुझे लगता है कि हम जहाँ भी संभव हो, स्लिपेज की घोषणा करते हैं। तीसरी तिमाही में, हमने गुडवाट्स को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया है और चौथी तिमाही में तुरन्त, हालांकि जेनसोल के विरुद्ध कोई चूक या कोई अतिदेय नहीं है, हमें सभी भुगतान प्राप्त हो गए थे, लेकिन धोखाधड़ी के कारण, हमने इसे पहले ही एनपीए घोषित कर दिया है। इसलिए जब आप किसी भी वित्तीय संस्थान के लिए बात करते हैं, तो यह नहीं हो सकता है कि किसी भी समय कोई स्लिपेज न हो। आपको यह देखना होगा कि कुल बही में से कितने प्रतिशत स्लिपेज हैं? चिंताएं हैं। मैं समझ सकती हूँ कि अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो हम स्वीकार करते हैं कि अगर कोई बड़ा मूल्यांकन चूक या ऐसा कुछ है, तो यह निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन 5,43,000 करोड़, 120 करोड़ की संपत्ति या 260 करोड़ का एनपीए होना, मुझे नहीं लगता कि इस स्तर पर निवेशकों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और वितरण क्षेत्र के बारे में, आपने कहा कि आपको वितरण कंपनियों की बैलेंस शीट की बढ़ती आवश्यकता और आकार की सराहना करने की आवश्यकता है, जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है। यदि हम वितरण कंपनी द्वारा वितरित की जा रही उत्पादन क्षमता को जोड़ रहे हैं, तो वे बिजली क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला को बड़े पैमाने पर जनता से जोड़ने वाला

अंतिम चरण हैं। इसलिए उनका आकार भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने एलपीएस के बाद आरडीएसएस के तहत पर्याप्त कदम उठाए हैं, आप जानते हैं, कि जनरेटर बकाया के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है, जिससे बिजली क्षेत्र के लिए मूल्य श्रृंखला में भावनाओं में सुधार हुआ है। हम खुद देख रहे हैं कि जनरेटर के लिए फंडिंग हो रही है। हम हैं, वे हैं, उनके पास फंड की भरमार है। वे अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आरबीपीएफ दिया जाता है, तो यह केवल एक परिक्रामी प्रकार की सुविधा है और यह धन का बहुत ही अल्पकालिक कुप्रबंधन है। आरडीएसएस के तहत, हम सरकारी विभाग के बकाए के भुगतान पर जोर दे रहे हैं, हम सब्सिडी बकाए के समय पर भुगतान पर जोर दे रहे हैं जो इस क्षेत्र की व्यवहार्यता में सुधार करने में मदद कर सकता है। लेकिन फिर भी, अभी भी कुछ खामियाँ हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। इसलिए वितरण क्षेत्र के लिए कदम दर कदम सुधार किए जा रहे हैं।

प्रशांत:

साथ ही, सिर्फ माफ़ी नहीं, बल्कि पहले उत्तर पर एक छोटा सा अनुवर्ती। क्या हमें इसे घर्षण के रूप में समझना चाहिए? आपके पास एनआईएम संपीड़न का कुछ हिस्सा हो सकता है। और फिर एक विलंबित सुधार की तरह जब आपके फंड की लागत भी बढ़ने लगती है। क्या हमें इसके बारे में इस तरह से सोचना चाहिए? क्योंकि आपके परिसंपत्ति पक्ष को पूर्व भुगतान दबाव को रोकने के लिए फिर से मूल्यांकित किया जा सकता है, जबकि आपके देयता पक्ष को केवल आपकी देनदारियों की परिपक्वता के आधार पर समय के साथ फिर से मूल्यांकित किया जाएगा। क्या इसे इस तरह से समझा जाना चाहिए, या, हमें इसके बारे में कैसे सोचना चाहिए?

परमिंदर चोपड़ा:

मुझे नहीं लगता कि आप निकट भविष्य में यह देख पाएंगे कि हम अपने प्रसार स्प्रेड गाइडेंस को बनाए रखने में सक्षम होंगे।

प्रशांत:

धन्यवाद।

तुलनाकर्ता:

हाँ। मेरे दाईं ओर बैठे सज्जन। हाँ, हाँ। कृपया आगे बढ़ें। हाँ।

पुनीत:

मैक्केरी से पुनीत। स्प्रेड कम्प्रेसन बिट पर। यह मानते हुए कि, आप जानते हैं, आप फंड की लागत में गिरावट देखने के बाद इसे पास कर देते हैं। और बैंकों को एक फायदा है क्योंकि रेपो दर में गिरावट तत्काल है, वे ऐसा कर सकते हैं, यही कारण है कि हम 14-13% से 11% की तरह स्प्रेड गाइडेंस कर रहे हैं, क्योंकि बैंकों को इसे जल्दी से पास करने में लाभ

है और, आप जानते हैं, खुदरा एसएमई विकास के साथ, हाल की तिमाहियों में कुछ गिरावट देखी गई है। वे यहां ध्यान केंद्रित करेंगे या केवल स्प्रेड गाइडेंस में गिरावट को समझना चाहेंगे क्योंकि, कैपेक्स आउटलुक काफी सकारात्मक है। तो हाँ यह पहले बिट पर है। दूसरा, हम जो चार्ज करते हैं और बैंक जो अक्षय परियोजना पर चार्ज करते हैं, उसके बीच दर अंतर क्या है? यदि यह पिछले चक्र की तरह है, तो मुझे पता है कि यह 100 बीपीएस से अधिक था। अच्छा। और क्या यह इस चक्र में नीचे आया है, उस बिट पर। और तीसरा, डिस्कॉम के मोर्चे पर, आपने उल्लेख किया कि 55% संवितरण, आप जानते हैं, डिस्कॉम के लिए किया गया है। इसकी प्रकृति क्या है? क्या यह मुख्य रूप से आरबीपीएफ की तरह है, जैसा कि आप जानते हैं, आरईसी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि इसका एक बड़ा हिस्सा आरबीपीएफ की ओर था, इसलिए पुनर्भुगतान काफी अस्थिर है। और अगर ऐसा है, तो क्या 10-11% भी जोखिम में है। हाँ।

परमिंदर चोपड़ा:

तो ऐसे बहुत से कारण हैं, जिनके लिए आप उस चीज़ को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, एक कारक ब्याज दर का है। तो विकास मैंने आपको बताया कि हम पहले भी एलपीएस के लिए संवितरण कर रहे हैं। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे डिस्कॉम अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर रहे हैं, निश्चित रूप से वे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को भी कम करना चाहेंगे, एक बार जब उन्हें संबंधित राज्य सरकार से समय पर पैसा मिल जाए या उनके टैरिफ में संशोधन हो जाए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, हमने कहा कि हमारी विकास मार्जिन वृद्धि, प्रक्षेपवक्र पिछली अवधि की तुलना में केवल 1% हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हम एक अंक या कुछ के नीचे आ गए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ब्याज दर की इसमें कोई भूमिका है। बैंक और पीएफसी ब्याज दर परिदृश्य द्वारा ऋण देने के बीच अंतर। यह हमेशा रहेगा। बैंकों के पास तक पहुंच है, जो हमारे पास नहीं है। उनके पास पहुंच है और वे जीसेक में निवेश करते हैं, वे अन्य में निवेश करते हैं और उनके पास एक और कारक है कि वे उच्च दर पर खुदरा शुल्क ले सकते हैं। आम तौर पर, हमने देखा है कि बैंकों द्वारा खुदरा ऋण, उच्च दर पर दिया जाता है। इसलिए वे उस ऋण की भरपाई करके शायद बुनियादी ढांचे या परियोजना के लिए बहुत अच्छी दर दे सकते हैं, जहाँ राजस्व सुव्यवस्थित है। इसलिए यह पीएफसी और बैंकों के बीच काम करने में एक बुनियादी मॉडल अंतर है, जबकि पीएफसी के पास ऐसा नहीं है, हम उस मामले में बैंक से उधार ले रहे हैं, जहाँ वे हमसे कम से कम एमसीएलआर या एमसीएलआर से थोड़ा कम शुल्क ले रहे हैं, यह अंतर आज भी है। यह कल भी था। और मुझे लगता है कि आगे भी यह अंतर बना रहेगा। लेकिन व्यवसाय और अवसर इतने बड़े हैं कि कोई भी एक वित्तीय संस्थान इसका ध्यान नहीं रख सकता। समूह मानदंडों और एकल कंपनी मानदंडों के अलावा बैंकों की अपनी क्षेत्रीय सीमाएँ हैं; वे एक ही समूह को विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऋण दे रहे हैं, लेकिन वे पूंजी समूह हैं। इसलिए वे सभी कारक भूमिका निभाएंगे और मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के लिए व्यवसाय में सभी के पास पर्याप्त हिस्सा है।

पुनीत:

क्या इससे आप अंतर का आकलन कर सकते हैं, मान लीजिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पीएफसी द्वारा ली जाने वाली दरों में कितना अंतर है?

परमिंदर चोपड़ा:

देखिए, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए बैंकों द्वारा कोई मानक दर नहीं रखी गई है। और हमारे लिए, दर 8.75 से शुरू होती है और उधारकर्ता की रेटिंग के आधार पर तय होती है।

तुलनाकर्ता:

हाँ, आप आगे बढ़ सकते हैं।

भोजवानी:

मेटा से भोजवानी, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी प्रस्तुति से पहले, एक ऑडियो वीडियो क्लिप थी जिसे बार-बार दिखाया जा रहा था। यह वास्तव में उल्लेखनीय है। 39 वर्षों में, आपकी कंपनी ने जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं और बिजली उत्पादन, वितरण और ट्रांसमिशन क्षेत्रों के सभी पहलुओं में पूरी तरह से स्थापित है। और आपकी प्रस्तुति में, आपने कई चीजों पर प्रकाश डाला, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक आपने कहा कि 15 डिस्कॉम को अपग्रेड किया गया है, यह अपग्रेडेशन स्मार्ट मीटर की स्थापना और उपयोग के कारण है, जो मेरा विचार था और दूसरा यह कि 13 डिस्कॉम को डाउनग्रेड किया गया है, इसलिए अपग्रेड और डाउनग्रेड के कारण और एक भाग और दूसरा भाग बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता पर है, ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस क्षमता को अक्षय ऊर्जा विकास के अनुरूप और अनुपात में बढ़ाने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं हैं। तो इस पर कोई विचार?

मनोज शर्मा:

वितरण क्षेत्र में डाउनग्रेड और अपग्रेड के बारे में। रेटिंग काफी व्यापक है और हमारे पास वित्तीय प्रदर्शन से जुड़ा लगभग 75% वेटेज है। इसमें मुख्य रूप से सरकार से सब्सिडी सहायता, दक्षता में सुधार, उनके प्रदर्शन पर पड़ने वाला प्रभाव और उनके एटीएंडसी घाटे में कमी शामिल है, इन सभी संयुक्त कारकों से हमने बड़े पैमाने पर सुधार देखा है, आरडीएसएस की शुरुआत के बाद यह प्रवृत्ति रही है, हमने अंतर के संदर्भ में सुधार और एटीएंडसी घाटे के संदर्भ में सुधार देखा है और यही कारण है और साथ ही कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो फिसल गए हैं या जो केवल इसे बनाए रख रहे हैं। इसलिए एक कारण के रूप में, हमने कुछ राज्यों या डिस्कॉम को डाउनग्रेड करते हुए देखा है, लेकिन बड़े पैमाने पर हमने वितरण क्षेत्र में सुधार होते देखा है।

परमिंदर चोपड़ा:

इसलिए डाउनग्रेड और अपग्रेड एक ही पैरामीटर पर काम करते हैं, क्योंकि यह एक मानक तंत्र है जहाँ हम कहते हैं कि यदि किसी विशेष डिस्कॉम के प्रदर्शन में सुधार हुआ है, तो उन्हें उच्च अंक मिलेंगे। और यदि यह पिछले वर्ष की तुलना

में बेहतर नहीं है, तो इसे डाउनग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई कारक हैं जिनके आधार पर इन्हें ध्यान में रखा जा रहा है।

भोजवानी:

नवीकरणीय ऊर्जा के मोर्चे पर बैटरी और ऊर्जा भंडारण क्षमता के बारे में, क्या हम नवीकरणीय ऊर्जा की बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता में कोई सीमा नहीं देख रहे हैं? संभवतः यही एक कारण है कि नवीकरणीय ऊर्जा का विकास अभी भी उतना नहीं हो पाया है जितना कि हम सौर या पवन ऊर्जा का दोहन करने में सक्षम हैं।

परमिंदर चोपड़ा:

जैसा कि मैंने अपनी आरंभिक टिप्पणियों में आपको बताया था, आज की तिथि तक स्थापित क्षमता का लगभग 45% नवीकरणीय क्षमता है, लेकिन नवीकरणीय क्षमता की मूल प्रकृति, नवीकरणीय क्षमता की आंतरायिक प्रकृति, जो ग्रिड की स्थिरता पर प्रभाव डाल सकती है, भंडारण प्रणाली के बारे में पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती है, यही कारण है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दो घंटे का भंडारण अनिवार्य कर दिया है, चाहे वह बैटरी भंडारण के माध्यम से हो या पंप भंडारण के माध्यम से। पंप भंडारण की तुलना में बैटरी भंडारण को लागू करना तेज़ है, जिसमें परियोजना पूरी होने की अवधि, अवधि लग सकती है, जिसकी अपनी परियोजना पूरी होने की अवधि, अवधि होती है। फिर अगला कारक लागत आता है, इसलिए लागत हमने लागत में कमी आते देखी है। हमने चर्चा की है कि यह 6-८ तक आ गई है। यानी बिना वीजीएफ के। यदि हम वीजीएफ को ध्यान में रखते हैं, तो यह अब पांच फिर भी इसमें कमी आने की गुंजाइश है, लेकिन इस स्टोरेज सुविधा के साथ अधिक से अधिक नीलामी होने के कारण, मुझे लगता है कि आपूर्ति कारक कीमत के पक्ष में काम करने जा रहा है, और फिर हम पैमाने की कुछ अर्थव्यवस्थाएं प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि हमने सौर प्रणाली पैनलों में देखा है, जो मूल रूप से बहुत अधिक लागत पर आ रहे थे और फिर धीरे-धीरे लागत कम हो रही थी। और इसी तरह, हम बैटरी स्टोरेज के लिए उम्मीद कर रहे हैं। यह वापस जा सकता है।

भोजवानी:

धन्यवाद मैम और शुभकामनाएं।

तुलनाकर्ता:

धन्यवाद। एक आखिरी सवाल लीजिए। हाँ। धन्यवाद।

अविनाश:

एमके से अविनाश। इसके अलावा कुछ सवाल भी हैं। पहला, स्टेज एक और दो पर इस बड़ी हुई प्रावधान कवरेज की व्याख्या क्या है, क्या यह अंतर्निहित परिसंपत्ति, गुणवत्ता सुरक्षित है, या क्या यह किसी तरह से किसी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग

प्रावधान के लिए तैयारी कर रहा है? ऐसा नहीं है, यह एक है। और दूसरा, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 2.58% प्रसार में। क्या उस मामले में केएसके महानदी 1200 करोड़ की ब्याज वसूली पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा है, तो अंतर्निहित, आप जानते हैं, उस पृष्ठभूमि में आपके पिछले स्प्रेड 2.5 से कम है। मेरा मतलब है, अगले साल, 2.5 स्प्रेड गाइडेंस जोखिम में है? धन्यवाद।

परमिंदर चोपड़ा:

हमने दूसरे चरण में प्रावधान को औसतन 0.58 से बढ़ाकर 1.85% कर दिया है। तो मूल रूप से भारतीय रिजर्व बैंक से कुछ स्प्रेड गाइडेंस मिला था और पीएफसी ने कुछ विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। तो इस तरह हमने दूसरे चरण के खाते में कवरेज को औसतन बढ़ाया है। आपके दूसरे प्रश्न पर, जब हम स्प्रेड पर काम कर रहे हैं, तो मैं आपको आश्चस्त कर सकता हूँ कि हमने उस उद्देश्य के लिए केएसए महानदी मामले में ब्याज को ध्यान में नहीं रखा है। तो यह उस सीमा तक हमारे भविष्य के गाइडेंसको प्रभावित नहीं करने वाला है। धन्यवाद।

तुलनाकर्ता:

देवियों और सज्जनों, आपकी सक्रिय भागीदारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

और मैं इस अवसर पर आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर आज दोपहर यहाँ हमारे साथ चाय पीने और एक प्यारी शाम बिताने के लिए आए। एक बार फिर से धन्यवाद।

परमिंदर चोपड़ा:

धन्यवाद।